

## स्पॉटलाइटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर नविश

यह एडिटरियल 19/11/2022 को 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में प्रकाशित "The Infrastructure Imperative" लेख पर आधारित है। इसमें भारत के अवसंरचना क्षेत्र को सशक्त करने से संबंधित प्रमुख चुनौतियों और उन्हें दूर करने के लिये किये जा सकने वाले उपायों के बारे में चर्चा की गई है।

### संदर्भ

आधारभूत संरचना या अवसंरचना क्षेत्र (Infrastructure sector) भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये एक प्रमुख चालक है। यह क्षेत्र भारत के समग्र विकास को आगे ले जाने के लिये प्रमुख रूप से उत्तरदायी है और सरकार द्वारा इस पर गहन ध्यान दिया जाता है। देश भर में आधारभूत संरचना परियोजनाओं को सुवर्धित बनाने के लिये केंद्र के साथ-साथ राज्य स्तर पर कई पहल की गई है।

- लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट, अत्याधुनिक आधारभूत संरचना निर्माण के मार्ग में अभी भी कई बाधाएँ हैं। सतत उच्च विकास और एक प्रतिसिपेक्षित वनिरिमाण क्षेत्र की ओर भारत की राह सुदृढ़ और विश्वसनीय राष्ट्रीय आधारभूत ढाँचे से होकर ही गुज़रेगी।


### भारत में अवसंरचना का वर्तमान परिदृश्य

- 'इंफ्रा-डेफिसिट इंडिया'**: भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा (ब्राजील के बाद) अवसंरचनागत घाटा रखने वाला देश है क्योंकि इसने 1990 के दशक की शुरुआत से ही 6% से अधिक की तीव्र गति से विकास किया है लेकिन आपूर्ति में अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है।
  - विश्व बैंक की **'भारत की शहरी अवसंरचना आवश्यकताओं का वित्तपोषण' (Financing India's Urban Infrastructure Needs) शीर्षक रिपोर्ट** के अनुसार, वर्ष 2036 तक 600 मिलियन लोग भारत के शहरी क्षेत्रों में रह रहे होंगे, जो जनसंख्या के 40% भाग का प्रतिनिधित्व करेंगे।
    - इससे भारतीय शहरों की पहले से ही तनी हुई शहरी अवसंरचना और सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है।
    - वर्तमान में भारतीय शहरों की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं का महज 5% ही निजी स्रोतों के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है।
  - अवसंरचना क्षेत्र का महत्त्व**:
    - अवसंरचना क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास के लिये एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह टाउनशिप, हाउसिंग, बलिट-अप इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण विकास परियोजनाओं जैसे संबंधित क्षेत्रों के विकास को संचालित करता है।
    - वैश्विक नविशकों ने आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिये भारत को अपने शीर्ष गंतव्य स्थलों में से एक के रूप में देखना शुरू कर दिया है। भारत अपने युवा उभार, मध्यम वर्ग के उदय और विशाल घरेलू बाज़ार के दम पर अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर उच्च प्रतफल या रटर्न दर की की पेशकश करता है।
  - संबंधित पहलें**:
    - सरकार ने वित्त वर्ष 2020-25 की अवधि के लिये अवसंरचना विकास को समर्थन देने हेतु **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)** शुरू की है, जहाँ शहरी अवसंरचना प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है।
    - सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिये आधारभूत संरचना परियोजनाओं की समन्वित योजना और नषिपादन के उद्देश्य से महत्त्वाकांक्षी गति शक्ति योजना भी शुरू की है।
    - राष्ट्रीय नविश और अवसंरचना कोष** (National Investment and Infrastructure Fund- NIIF) एक सरकार समर्थित इकाई है, जो देश के अवसंरचना क्षेत्र को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिये स्थापित की गई है। इसे दिसंबर 2015 में श्रेणी-II वैकल्पिक नविश कोष के रूप में स्थापित किया गया था।
    - नवंबर 2021 में **भारत, इजराइल, अमेरिका और यूई** (I2U2) ने क्षेत्र में अवसंरचना विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने तथा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिये एक नया चतुरभुज आर्थिक मंच स्थापित किया।
    - मार्च 2021 में भारत में अवसंरचना परियोजनाओं को नधि देने के लिये **राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक** (National Bank for Financing Infrastructure and Development- NaBFID) की स्थापना के लिये संसद में इस आशय का एक वधियक पारित किया गया।

### संबंधित चुनौतियाँ

- भारत की सबसे बड़ी चुनौती विशाल अवसंरचनागत वित्तीय अंतराल है, जिसके जीडीपी के 5% से अधिक होने का अनुमान है।
- भूमि अधिग्रहण, आक्रामक बोली लगाना और गैर-नष्पादित परसिंपत्तियों अवसंरचनात्मक PPPs (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) के लिये प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
- भारत तनावग्रस्त परसिंपत्तियों के उच्च स्तर का सामना कर रहा है और अर्थव्यवस्था के भविष्य के विकास के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये ऋण वृद्धि को आधार के रूप में बहाल करने की आवश्यकता है।
  - बैंकों में तनावग्रस्त परसिंपत्तियों के साथ-साथ बैंकों की छोटी पूंजी के कारण इन परसिंपत्तियों पर अतिरिक्त और संभावित रूप से गंभीर कष्टों की स्थिति बन सकती है।
- इसके अलावा, क्रेडिट ब्याज दरों की स्थिरता की कमी से क्षेत्र में निवेश के लिये एक उल्लेखनीय जोखिम उत्पन्न हुआ है।
  - यह तथ्य कि भारत में अवसंरचना निवेश आम तौर पर USD पर अपेक्षित प्रतफल/रिटर्न पर आधारित होता है न कि उपयोगकर्ता शुल्क पर, एक असंतुलन का सृजन करता है और देश में विदेशी अवसंरचना निवेश के कुल प्रवाह को प्रभावित करता है।

# Roadblocks in key sectors



## HIGHWAYS

- Delays in land acquisition; lenders stop lending midway
- Tendering of projects to low-traffic entity
- Unclear exit policy for road developer; NHAI is a developer as well as the regulator which causes a conflict of interest in case of arbitration so there is a need for a clear distinction of roles for NHAI

## PORTS

- Multiple changes in tariffs setup by the Tariff Authority for Major Ports make it difficult to evaluate the cost of projects
- Delays in tariff fixation

## POWER

- Coal block deallocation causing execution delays and losses to project developers
- New auction-based coal linkage approved by government in 2017, uncertainty remains regarding the validity of old contracts
- Inconsistency in the interpretation of PPA
- Inconsistency in Central & State regulation, for instance, the Central electricity Act allows open access, but State governments do not adhere to it causing the problem in execution
- Unstable financial health of State utility causes a delay in the payment cycle

## AIRPORTS

- Lack of consistency in tariff methodology and concession tariff framework
- Switching from single till tariff method to hybrid till creates difficulty in assessing the cost of projects
- Delays in the passage of tariff orders cause problems in the timely execution of projects

## WIND

- Inconsistent policy at Central and State govt level
- Accelerated depreciation leads to non-viability
- State regulators do not honour renewable purchase obligation

## TELECOM

- Lack of predictability
- Inconsistent policy and regulatory framework; govt refuses to honour PPAs signed earlier
- Aggressive bidding to some extent

## GREENFIELD PROJECTS

- Land acquisition delay
- Nature of developers have been contractors which leads to low-cost bidding making the project unviable
- Bank loans are given out for 10/15/18 years but the interest reset clause poses a high risk on overall investment return evaluation, sometimes 8% interest rates are increased up to 14-15% rendering the project unviable

## BROWNFIELD PROJECTS

- Government questions the validity of existing projects (eg, with rates of solar energy slashing, will the contracts entered on higher tariffs remain valid or not?)

- There is a strong need for the ability to have more credible infrastructure developers and partners

## UNIFIED LOGISTICS INTERFACE PLATFORM (ULIP) IS DESIGNED TO ENHANCE EFFICIENCY AND REDUCE THE COST OF LOGISTICS BY CREATING A TRANSPARENT, ONE-WINDOW PLATFORM

## अवसंरचना क्षेत्र को सशक्त करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- नीति/नियामक ढाँचे में नरिंतरता सुनिश्चित करना: निविदा प्रक्रिया में एक बेहतर नियामक वातावरण और नरिंतरता की आवश्यकता है। विभिन्न सरकारी विभागों में नरिंतरता और नीतित्त सामंजस्य की कमी को प्राथमिकता से संबोधित किया जाना चाहिये।
  - तनावग्रस्त परसिंपत्तियों की समस्या से निपटने के लिये सरकार और RBI के मध्य एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिये। गैर-नष्पादित संपत्तियों, PSUs के पुनरुद्धार के लिये सभी क्षेत्रों में एक समरपत्ति नीतिका निर्माण करने की आवश्यकता है।

- **उचित उपयोगकर्ता शुल्क:** अवसंरचन वित्तपोषण, अवसंरचना सेवा प्रदाताओं की वित्तीय व्यवहार्यता और पर्यावरण एवं संसाधन उपयोग संवहनीयता को बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है।
  - उपयोगकर्ता शुल्क महत्वपूर्ण हैं क्योंकि देश भर के कई क्षेत्रों में आंशिक रूप से शून्य या बहुत कम उपयोगकर्ता शुल्क के कारण कीमती संसाधनों (जैसे भूजल) का अत्यधिक उपयोग एवं अपव्यय होता है।
  - उचित उपयोगकर्ता मूल्यों से प्रेरित पर्यावरणीय संवहनीयता एवं संसाधन उपयोग दक्षता के अलावा इस नीति प्राथमिकता में अपार संसाधन सृजन क्षमता भी है।
- **अवसंरचना का स्वायत्त वनियमन:** चूँकि भारत और विश्व नज़ी भागीदारी के लिये अधिकाधिक क्षेत्रों को खोल रहे हैं, नज़ी क्षेत्र अनविरय रूप से स्वायत्त अवसंरचना वनियमन की मांग करेगा।
  - विश्वव्यापी प्रवृत्ति बहु-क्षेत्रीय नियमकों की ओर है क्योंकि आधारभूत संरचना क्षेत्रों में नियामक भूमिका आम है और ऐसे संस्थान नियामक क्षमता का निर्माण करते हैं, संसाधनों का संरक्षण करते हैं और नियामक कब्जे को रोकते हैं।
- **संपत्ति पुनर्चक्रण (AR) और BAM:** BAM (Brownfield Asset Monetisation) का मूल विचार ब्राउनफील्ड AR के माध्यम से अवसंरचनागत संसाधनों को बढ़ाना है ताकि डी-रिस्कड ब्राउनफील्ड सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों में बंधी धनराशि को मुक्त करके त्वरित ग्रीनफील्ड निवेश किया जा सके।
  - इन परिसंपत्तियों को एक ट्रस्ट (InvITs) या एक कॉर्पोरेट संरचना (TOT मॉडल) में स्थानांतरित किया जा सकता है, जो कैपिटल कंसल्टिगेशन (जो इन अंतरनिहित परिसंपत्तियों से भवषिय के नकदी प्रवाह के मूल्य पर कब्जा करता है) के बजाय संस्थागत निवेशकों से निवेश प्राप्त करता है।
  - भारत के पास अवसंरचना क्षेत्रों में ब्राउनफील्ड संपत्तियों का एक बड़ा भंडार है।
- **घरेलू फंड का उपयोग:** भारतीय पेंशन फंड जैसे घरेलू स्रोत जो नषिक्रयि पड़े हुए हैं, यदा कुशलता से उपयोग किये जाएँ तो इस क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मल सकता है।
  - भारत अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिये घरेलू धन के कुशल उपयोग पर कनाडा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं ऐसे अन्य देशों के अभ्यासों का अनुकरण कर सकता है।
- **वैश्विक नेतृत्व का लाभ उठाना:** भारत दसिंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है। वभिनिन G20 देशों ने अपनी अध्यक्षता में अवसंरचना के लिये एजेंडा निर्धारित किया है, जैसे कि परिसंपत्ति वर्ग के रूप में अवसंरचना के लिये रोडमैप (अरजेंटीना, 2018), गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना निवेश के सिद्धांत (जापान, 2019), इफ्राटेक (सऊदी अरब, 2020) और प्रतफिल/रकिवरी के लिये संवहनीय अवसंरचना का वित्तपोषण (इटली, 2021)।
  - G20 की अध्यक्षता भारत के लिये एक अवसर है कि वह स्वयं के लिये और विश्व के लिये अवसंरचना एजेंडे को निर्धारित करे।

**अभ्यास प्रश्न:** "वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अवसंरचना विकास समय की आवश्यकता है।" टपिपणी कीजिये।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

???????????????? ?????:

Q 1. 'राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी अवसंरचना कोष' के संदर्भ में, नमिनलखिति में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (वर्ष 2017)

1. यह नीति आयोग का एक अंग है।
2. वर्तमान में इसके पास 4,00,000 करोड़ का कोष है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (D)

Q 2. भारत में "सार्वजनिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना" शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है (वर्ष 2020)

- (A) डिजिटल सुरक्षा बुनियादी अवसंरचना
- (B) खाद्य सुरक्षा बुनियादी अवसंरचना
- (C) स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा हेतु बुनियादी अवसंरचना
- (D) दूरसंचार और परविहन बुनियादी अवसंरचना

उत्तर: (A)

????? ????????

Q. अधिक तीव्र और समावेशी आर्थिक विकास के लिए बुनियादी अवसंरचना में निवेश आवश्यक है।” भारत के अनुभव के आलोक में चर्चा करें।  
(वर्ष 2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/spotlighting-infrastructure-investments>

